State/Union Territory	CD Ratio (Percent)
SOUTHERN REGION	72.3
1. Andhra Pradesh	72.1
2. Karnataka	68.2
3. Kerala	44.3
4. Tamil Nadu	96.1
5. Lakshadweep	10.0
6. Pondicherry	35.9
ALL INDIA	55.5

Thrust of Economic Reforms

1744. SHRI KULDIP NAYYAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the economic reforms initiated during his tenure and the concrete steps taken in that regard; and

(b) what is the general policy and thrust in this direction?

THE MINISTER FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) A number of initiatives were announced in the Union budget 1998-99 to stimulate growth and investment in agriculture, industry and infrastructure. The initiatives concerned rural credit, small scale industry, income tax (New Schemes such as 'SARAL' and 'SAMADHAN' introduced for the first time), housing, infrastructure, fiscal and public sector capital market. Further, measures have been announced in the areas of export-import and credit policies, disinvestment, opening up of the insurance sector, investors protection and measures to restore investors confidence, formulation of a new inter-net and Telecom policies to provide state of the art technology, nation wide telecommunication net work and rural telephone services.

Further, policy initiatives have been taken to make India a Global player in Information Technology and one of the largest generators and Exporters of software in the world within ten years.

कम्पयूटरों की खराबी का भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यो पर प्रभाव

1745. **श्री शिवू सारेने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले एक महीने से भारतीय रिजर्व बैंक के कंप्यूटरों में खराबी के कारण करोड़ो और अरबों रूपयों के कारोबार आयात-निर्यात-चैंक मंजूरी आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ा हैं और उससे संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कंप्यूटर में उक्त खराबी के कारण चैंक मंजूरी का काम पूरी तरह हाथ से किया जा रहा हैं;

(घ) क्या सरकार इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती हैं, और

(ड.) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि नई दिल्ली बैकर्स ट्रेडिंग हाउस में 9,10 तथा 11 नवम्बर, 1998 को स्थानीय समाशोधन में चैंकों का समाशोधन अस्थाई रूप से अस्त-व्यस्त हो गया था। परिणामस्वरूप, उक्त तारीखों में निपटान में विलम्ब हुआ। 10,11 तथा 12 नवम्बर, 1998 को देर शाम तक ही वितरण के लिए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सकी। अधिक मूल्य वाले (और प्रतिफल) अंतरबैंक समाशोधन का निपटान सामान्य रूप से किया गया। 13 नवम्बर, 98 के बाद से स्थानीय समाशोधन तथा इसके वितरण सामान्य रूप से निपटाए गए। चैंकों का निपटान हाई स्पीड रीडर्स सार्टर प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा हैं न कि हाथों से।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक की अर्द्धवार्षिक ऋण नीति

1746. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी छमाही ऋण नीति की घोषणा की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके दूरगामी परिणामों की समीक्षा की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उद्योगों की सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 30 अक्तूबर, 1998 को "1998-99 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा" सम्बन्धी एक विवरण जारी किया।

(ख) से (घ) ऊपर उल्लिखित नीति में वे उपाय शामिल होते हैं जो मूलत: दीर्घावधिक स्वरूप के होते हैं। इन उपायों का उद्देश्य सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप पूंजीगत प्रर्याप्तता के निर्धारण और अन्य विवेकपूर्ण मानदण्डों को सुदृढ़ बनाकर मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाना हैं। ये उपाय भविष्यगामी स्वरूप के हैं और एक निश्चित समयावधि में चरणबद्व रूप से कार्यान्वित किए जाएंगे।

बैंकिंग प्रणाली में नकदी-निधि की स्थिति सन्तोषजनक हैं और औद्योगिक क्षेत्र के ऋण सम्बन्धी आवश्यताएं पर्याप्त रूप से वहन की जा सकती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक अर्थात् 6 नवम्बर, 1998 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए संसाधनों के कुल प्रवाह में 19,701 करोड़ रूपए की वृद्वि प्रदर्शित हुई हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 15,338 करोड़ रूपए की वृद्वि की तुलना में अधिक हैं। पूर्वोवत को ध्यान मे रखते हुए अल्पावधि उपायों अर्थात् बैक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात और रिपो दर में किसी परिवर्तन की घोषण नहीं की गई हैं।

मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए उपाय

1747. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य वृद्वि की समस्या को हल करने के लिए कुछ नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों के कारण मूल्य वृद्वि में कितने प्रतिशत गिरावट आयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए समुचित कदम कब तक उठाने का विचार रखती हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई हैं और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ.जी.एल. के तहत इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई हैं।
- नेफैड को आर्थिक सहायता प्रदत्त बिक्री के लिए प्याज की अधिप्राप्ति करने के लिए कहा गया।
- भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को अधिकृत किया गया हैं।
- ओ.जी.एल. के तहत दालों के आयात की अनुमति दी गई हैं और दालों के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क को समाप्त कर दिया गया हैं।
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों/संघ शसित प्रदेशों के लिए 1.5 लाख टन खाद्य तेल की डिलीवरी सुनिश्चित की गई हैं।
- वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा तेल का आयात करने पर 4 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
- मूल्य स्थिति पर निगाह रखने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवो की समिति (सी.ओ.एस.) की नियमित रूप से बैठक होती हैं।

मंत्रिमण्डल सचिव ने आश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्वि को रोकने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। तदन्तर, 27.11.98 को हुई मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक में अनेक कार्रवाई संबंधी मुद्दे तय किए गए, जिन पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही हैं।

(ख) और (ग) अधिकतर सब्जियों की कीमतों में दिसम्बर, में अद्योगामी प्रवृत्ति दिखाई देनी शुरू हो गई हैं और प्याज तथा आलूओं की कीमतों में पर्याप्त कमी आई हैं। इस कमी के आगे भी जारी रहने की सम्भावना हैं।

Transfer of IT Officials

1748. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Income Tax Officials have been transferred within three months affecting the ongoing investigation against a number of politicians; and